चीनी को डीकंट्रोल करने पर नहीं बनी सहमति

विजय गुप्ता

नई दिल्ली। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने को लेकर सरकार भले ही उद्योग जगत के सुर में सुर मिला रही हो, लेकिन किसान इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। गन्ना उत्पादक राज्यों की राय भी इस मामले में अलग-अलग है। इससे चीनी को नियंत्रण मुक्त करने को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की परेशानी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली यह समिति अगले माह तय समयसीमा में रिपोर्ट पेश करने के बजाए सरकार से समयावधि बढ़ाने की मांग कर सकती है।

समिति अब तक देश के प्रमुख गन्ना किसान संगठनों, राज्यों के प्रमुख सचिवों और गन्ना आयुक्तों से कई चरणों में वार्ता करने के साथ ही गन्ना उत्पादक राज्यों का दौरा भी कर चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ ही गन्ना उत्पादकों की भी अलग-अलग राय के चलते सहमति नहीं बन पा रही।

महाराष्ट्र की हां तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया खारिज

महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक रिजर्वेशन खत्म करने पर सहमत हैं। उनका तर्क है कि इससे किसानों को अपना गन्ना किसी भी मिल में बेचने की आजादी मिलेगी और किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य का फायदा मिलेगा। वहीं यूपी के उत्पादकों ने रिजर्वेशन खत्म करने का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि इससे मिलों का कार्टेल बन जाएगा और किसानों को गन्ना बेचने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा।